दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 11 अक्टूबर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 15

महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यों को अब अर्धसैनिक बलों की तैनाती पड़ेगी महंगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि अब अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ने पर राज्यों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर अगले 5 साल के लिए नई दर तय कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए पांच साल के लिए तय की गई खर्च की रकम के संबन्ध में सभी राज्यों को पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों को अर्धसैनिक बलों की जरूरत होगी,उनको अब अब 10 से 15 फीसदी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। मसलन वर्ष 2018-19 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 13 करोड़ देने होंगें, वहीं हाई रिस्क और हार्ड शिप में एरिया के लिए 34 करोड़ सलाना देने होंगे। वर्ष 2023-24 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 22 करोड़ देने हैं, वहीं हाई रिस्क और हार्ड शिप में एरिया के लिए करीब 42 करोड़ सलाना देने होंगे। केन्द्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे राज्य हैं जिन पर अर्धसैनिक बलों का करोड़ों रुपये बकाया है जिन्होंने पिछले लंबे वक्त से पैसे नहीं चुकाए हैं।

राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कोर को कलर प्रदान किया

नासिक (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी एविएशन कोर को नासिक में गुरुवार को कलर प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आर्मी एविएशन कोर को विशिष्ट शौर्य और उल्लेखनीय सेवा के लिए 273 सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। इससे कोर के जवानों की असाधारण बहादुरी और जोश का पता चलता है और यह हमारी सशस्त्र सेनाओं के सभी सैनिकों और अधिकारियों के लिए एक आदर्श है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन में सोमालिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में कार्य करते समय इन्होंने हमारे देश के उत्कृष्ट राजदूतों की भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने आर्मी एविएशन कोर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके खून और बलिदान ने हमारी प्रभुसत्ता की रक्षा की और देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि आर्मी एविएशन कोर के सदस्य सबसे कठिन क्षेत्रों और खराब मौसम में सच्ची ताकत बनकर उभरते हैं। भारतीय सेना और देश को उन पर गर्व है।

एनएफएल ने भारत सरकार को 28.22 करोड़ का लाभांश दिया

नईदिल्ली (आरएनएस)। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार को 28.22 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रमोद मिश्रा ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी. वी. सदानंद गौडा को 28.22 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक सचिव छबीलेंद्र राउल, मंत्रालय तथा एनएफएल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि एनएफएल केंद्र सरकार को बेचे गए 490.58 करोड़ रुपए के शेयरों के बदले अब तक उसे कुल 1156.97 करोड़ रुपए का लाभांश दे चुकी है।

भाजपा सांसद चलाएंगे जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों व विधायकों सहित प्रदेश और जिलों के नेताओं को गांव-गांव जाकर जनसंख्या नियंत्रण पर जन-जागरण मुहिम चलाने को कहा है। यह जन-जागरण अभियान मौजूदा समय में चल रही गांधी संकल्प यात्रा के तहत 31 अक्टूबर तक किया जाना है। भाजपा मुख्यालय से पार्टी नेताओं को जारी यह निर्देश इस मायने में भी खास है कि कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने और तीन तलाक बिल के बाद से अटकलें लग रही हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफहो सकता है। आईएएनएस के पास मौजूद पार्टी के पत्र में कहा गया है, 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ मुद्दों पर बात की, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

भारत सौर ऊर्जा में पांचवें व पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर

नईदिल्ली (आरएनएस)। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने पर संशय जाहिर करने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया

नईदिल्ली। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में वर्ष 2022 तक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 1, 75,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने संबंधी क्रिसिल रिपोर्ट पर आधारित मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट पर खंडन जारी किया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त न करने संबंधी रिपोर्ट

आधारहीन है और वस्तुस्थिति को सही रूप से प्रदर्शित नहीं करती। सितम्बर 2019 के अंत तक भारत में 82,580 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की जा चुकी है और 31,150 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने के विभिन्न चरणों में है। 2021 की पहली तिमाही तक भारत 1,13,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना कर चुका होगा। यह लक्षित क्षमता का लगभग 65 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त 49,000 मेगावाट क्षमता की विभिन्न परियोजनाएं बोली के विभिन्न चरणों में हैं जिन्हें सितम्बर 2021 तक स्थापित कर दिया जायेगा। इससे कुल लक्ष्य के 87 प्रतिशत से अधिक क्षमता की स्थापना हो सकेगी। वर्तमान में 23,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बोली बाकी बची है और भारत को विश्वास है कि भारत 1,75,000 मेगावाट की क्षमता न सिर्फ स्थापित करेगा बल्कि इससे अधिक अच्छा प्रदर्शन करेगा।

मंत्रालय ने इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्यरत रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग, विकासक, निवेशक और अन्य भागीदारकों ने पारदर्शी निविदा प्रणाली और उचित दरों पर बिजली खरीद में सुविधा के लिए मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना की है। इसके फलस्वरूप सौर और पवन ऊर्जा के शुल्क में महत्वपूर्ण कमी देखी गई हैं। वर्ष 2016 में जहां पवन ऊर्जा 4.18 रुपए की दर पर थी वह गत वर्ष घटकर 2.43 रुपए रह गई और यह आज भी 2.75 प्रति यूनिट से कम है। सौर टेरिफ 4.43 रुपए प्रति यूनिट (वीजीएफ के साथ) से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट रह गई है।

मार्च, 2014 से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 138 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34,000 मेगावाट से बढ़कर 82,580 मेगावाट हो गई है। विश्वभर में भारत सौर ऊर्जा में पांचवें स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे और कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है।

मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर गुजरात में भूमि के आवंटन और राजस्थान में भूमि सुधार शुल्क मे बदलाव संबंधी मुद्दों का समाधान करने के प्रति तत्पर है। मंत्रालय भूमि आवंटन की समस्या से निपटने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करने की प्रक्रिया में कार्यरत है। इन पार्क में निर्धारित वितरण सुविधा होगी। ऐसा पहला पार्क एसईसीआई द्वारा गुजरात के

केंद्र की 150 ट्रेनों को निजी हाथों में देने की तैयारी

» तेजस एक्सप्रेस पहली निजी क्षेत्र के संचालन वाली ट्रेन

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद अब सरकार ने कई और ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें जल्द ही केंद्र सरकार करीब 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों का निजीकरण कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार इस तैयारी के लिए रेल मंत्रालय ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत से विचार विमर्श करके एक मेगा खाका तैयार कर लिया है जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले पिछले दिनों देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस को हरी झंडी देकर नई दिल्ली से लखनऊ तक के लिए शुरू किया गया है। सूत्रों की माने तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव को इस बारे में एक पत्र लिखकर 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण करने की प्रक्रिया पर सुझाव दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ ने रेलवे को शुरुआती चरण में 150 ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात कही है, जिसके लिए सचिव स्तर का एम्पावरड ग्रुप बनाया जाएगा, जो इस काम को अंजाम देंगे। इस एम्पावरड ग्रुप में नीति आयोग के सीईओ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, शहरी एवं विकास मंत्रालय के सचिव शामिल हो सकते हैं।

कोर्ट में पेश हुए राहुल, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

» मानहानि केस

सूरत (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान के संबंध में आपराधिक मानहानि केस का सामना कर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को सूरत कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में जब जज ने पूछा कि क्या आपको अपना गुनाह कबूल है, तो राहुल गांधी ने कहा- नहीं. मुझे गुनाह कबूल नहीं है. सूरत की सेशंस कोर्ट में अब 10 दिसंबर को इस केस की अगली सुनवाई होगी.

दरअसल, राहुल गांधी ने

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी के स्थानीय विधायक पुरनेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.

कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कथित रूप से कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सबका मोदी उप नाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है?'

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को समन जारी किया था. अदालत ने बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी की आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत की गई शिकायत को स्वीकार कर लिया था. यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है. जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी.

राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है.

ज्ञात हो कि केरल के वायानाड से सांसद राहुल गांधी को आरएसएस-बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ दायर इसी तरह के एक अन्य मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद में चल रही अदालती सुनवाई में भी शामिल होना है.

चार दिवसीय 38वां इंडिया कार्पेट एक्सपो आज से

वाराणसी (आरएनएस)। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) वाराणसी में 11-14 अक्टूबर तक 38वें इंडिया कार्पेट एक्सपो (वाराणसी में 15वां) का आयोजन करने जा रही है। यह एक्सपो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में सांस्कृतिक धरोहर और भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों और फ्लोर कवरिंग की बुनाई के कौशलों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ विदेशों से आने वाले कालीन के खरीददारों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इंडिया कार्पेट एक्सपो कालीन के अंतरराष्ट्रीय खरीददारों, क्रेता घरानों, क्रेता एजेंटों, आर्किटेक्ट्स

और भारतीय कालीन विनिर्माताओं तथा निर्यातकों के लिए मुलाकात करने और कारोबारी संबंध स्थापित करने का मंच है। यह एक्सपो साल में दो बार वाराणसी और दिल्ली में आयोजित किया जाता है।

इंडिया कार्पेट एक्सपो एशिया में लगने वाले विशालतम हस्तनिर्मित कालीन मेलों में से एक है। कालीन खरीदने वालों की आवश्यकता के अनुसार किसी भी तरह के डिजाइन, रंग, गुणवत्ता और आकार को अपनाने की विलक्षण भारतीय क्षमता ने उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद जाना-पहचाना नाम बना दिया है। यह उद्योग भारत के विभिन्न हिस्सों से ऊन, रेशम, मानव निर्मित फाइबर, जूट, कॉटेन और विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विविध मिश्रणों का उपयोग करता है। कार्पेट उद्योग में निर्माण और निर्यात दोनों के लिए ही वृद्धि की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यह उद्योग पर्यावरण के अनुकूल है और यह दुलर्भ और नष्ट हो जाने वाले ऊर्ज के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करता।

देशभर में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के 2700 सदस्य हैं और वाराणसी की विशाल कालीन निर्माता पट्टी पर इंडिया कार्पेट एक्सपो के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य विदेशों के सभी कालीन खरीददारों को कारोबार का अवसर चुनने का अनूठा अवसर प्रदान करना है। परिषद कालीन आयातकों साथ ही साथ विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए विशिष्ट कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

पीएम मोदी, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के विमान होंगे मिसाइलों से लैस

» वायुसेना के पायलटों की होगी जिम्मेदारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विमान को अब एयरफोर्स के पायलट ही उड़ाएंगे, जिनमें मिसाइले लगाई जाएंगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब इस विमान को एयर इंडिया के पायलट नहीं उड़ा पाएंगे। भारत के पास अगले साल जुलाई में दो कस्टमाइज्ड बी-777 प्लेन आएंगे अभी बी-747 हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यात्रा करते हैं। अब नए दो बी-777 विमानों को अगले साल जुलाई से एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। इनमें में नई मिसाइलें लगी होंगी जो आपातकाल की स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। साल 2020 जुलाई तक अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग दो नए बी-777 विमान भारत पहुंचाएगा। इन्हें सिर्फ एयरफोर्स के पायलट ही उड़ा पाएंगे। इनको एयरइंडिया-वन कहा जाएगा।

चिदंबरम व कार्ति की अग्रिम जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा ईडी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ईडी की अर्जी पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने 5 सितंबर को दिए गए विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत को मंजूरी दी गई थी। ईडी ने 5 सितंबर को दिए गए विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसमें चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत की मंजूरी दी गई थी। अदालत ने अग्रिम जमानत देते हुए चिदंबरम और उनके बेटे को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।

महाराष्ट्र-हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल

नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले कुछ दिनों से विदेश यात्रा पर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत लौट आए हैं और वह महाराष्ट्र एवं हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में 13 और 15 अक्टूबर को चुनाव बैठकों को संबोधित करेंगे। हरियाणा में वह 14 अक्टूबर को चुनाव बैठकों को संबोधित करेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले विदेश जाने के लिए राहुल गांधी आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होगा। भाजपा ने राहुल के विदेशी दौरों को लेकर उन पर कटाक्ष किया था।

छत्तीसगढ़ भवन में फेस्टिवल सेल की हस्तशिल्प प्रदर्शनी

» राज्य की कोसे सिल्क की साड़ियों की नजर आई धूम

नई दिल्ली (आरएनएस)। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में फेस्टिवल सेल के तहत हस्तशिल्प प्रदर्शनी और सेल लगाई गयी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बुनकर राज्य की खास पहचान कोसा सिल्क की साड़ियाँ लेकर पहुंचे हैं, जिनमें ट्राइबल आर्ट और एप्लिक वर्क दिख रहा है।

यहां गत 7 अक्टूबर से आरंभ हुई यह प्रदर्शन14 अक्तूबर तक लगाई गयी है, जिसमें टसर सिल्क में हैंड ब्लॉक वर्क, ट्राइबल आर्ट और एप्लिक वर्क आदि की कई वेराइटी की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। यहां कॉटन की चादर, नेचुरल डाई से तैयार कोसा सिल्क सहित अनेक वैराइटी मिल रहे हैं।

कारीगरों के द्वारा हाथों से बुने कपड़े अक्सर व्यक्तित्व की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि हैंडलूम के आइटम्स की हमेशा डिमांड रहती है। छत्तीसगढ़ में हैंडलूम को लेकर विशेष तरह का काम हो रहा है। साड़ी से लेकर कई तरह के ड्रेस मटेरियल बन रहे हैं, जिसे लेकर राज्य के कारीगर प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के बस्तर के शिल्पी कोसा सिल्क साड़ियां लेकर आए हैं। इन साड़ियों की खासियत है कि साड़ी पर मुरिया आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली, मान्यताएं आदि उकेरी गई हैं। वहीं रायगढ़ से आए कारीगर एप्लिक वर्क की साड़ियाँ लेकर आयें हैं, जिसमें कपड़े को काटकर डिजाइन तैयार किया जाता है। चांपा से आए गजानन्द देवांगन 19 साल कारीगरी से जुड़े हैं। उन्होने बताया कि कोसा टसर की साड़ियों पर लड़कियां बस्तर आर्ट बनाती हैं, कलर करने के लिए इसमें नैचुरल डाई का उपयोग किया जाता है। वहीं, बिलाईगढ़ से पहुंचे देवानन्द देवांगन ने कोसा तैयार करने की विधि बताते हुये कहा कि कोकून (कोसा धागे का कोवा) बस्तर और जगदलपुर के जंगलों में ज्यादा होता है। कोकून के अंदर स्थि त रेशम के कीड़े को मारकर सात दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उसे सोडा के साथ उबालकर फाइन धागा तैयार किया जाता है।